

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 06/2015

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला—बारां

(प्रार्थी)

बनाम

- 1—श्री धन्नालाल पुत्र श्री जगन्नाथ
- 2—श्री उदालाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति—माली नि. पाठेड़ा तह० बारां
- 3—श्रीमति केलाबाई (मृतक) पत्नि श्री प्रभूलाल पुत्री श्री जगन्नाथ जाति—माली नि. पाठेड़ा तहसील—बारां
- 3/1 श्री शिवराज पुत्र श्री प्रभूलाल
- 3/2 श्री हेमराज पुत्र श्री प्रभूलाल
- 3/3 श्रीमति गीताबाई पत्नि श्री मांगीलाल पुत्री श्री प्रभूलाल जाति माली नि. जलवाड़ा तह०—किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 व 2)
3. श्री राजेश जयन्त, अभिभाषक(अप्रार्थी कम 3/1 ता 3/3)

आदेश दिनांक— 31.03.2021

1— प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, बारां ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख०नं० 218 रकबा 0.07 है. किस्म गै.मु. खाल वाके ग्राम पाठेड़ा तहसील—बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068—71 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा रहे हैं, जिसके सम्वत् 2038—57 जमाबन्दी में खातेदार श्री जगन्नाथ पुत्र नोन्दा जाति—माली सा. देह पाठेड़ा तहसील—बारां के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2015—24 में गै.मु.खाल दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पिता को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा—16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक

02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये हैं।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 21.09.2015 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त भूमि आज से 65 साल पहले अप्रार्थीगण के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नोन्दाजी जाति माली निवासी पाठेड़ा को आवंटन हुयी थी तथा उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी खाल नाल नहीं है तथा काश्त योग्य है। उक्त आराजी के लगवां ही अप्रार्थीगण के खाते की अन्य आराजी स्थित है। अप्रार्थीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति हैं, जो काश्तकारी का कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। अतः रेफरेंस कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4— अप्रार्थी क्रम 3/1 ता 3/3 के अभिभाषक को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 14.08.2019 को जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया।

5— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान परोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

6— बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नोन्दाजी जाति माली निवासी पाठेड़ा तहसील-बारां को ग्राम पाठेड़ा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा किस्म गै.मु. खाल में से भूमि आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.खाल थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 218 रकबा 0.07 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म गै.मु.खाल दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन नियम विरुद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ

हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.खाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

7— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने परोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नोन्दाजी जाति माली निवासी पाठेड़ा तहसील-बारां भूमिहीन कृषक होने से, उन्हे उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये परोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.खाल थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु.खाल दर्ज है तो रेकार्ड दुरुस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण आवंटन पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर ख0नं0 218 रकबा 0.07 है0 बने हैं जो वर्तमान में सम्वत् 2068-71 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी मिल चुकी है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 65 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

8— हमने परोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015-24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा किस्म गै.मु.खाल खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नोन्दाजी जाति माली निवासी पाठेड़ा तहसील-बारां को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 218 रकबा 0.07 है0 बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. खाल खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरुद्ध हुआ है।

9— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2015-24 में किस्म गै. मु. खाल खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 218 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.खाल बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. खाल दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के पिता को विधि विरुद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10— परिणास्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, बारां का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम पाठेड़ा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.खाल, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 137 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा किस्म गै.मु.खाल से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

11— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.खाल वाके ग्राम पाठेड़ा तहसील-बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द-बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां